

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

04/2018

6-8-2018

- 1-कालूराम दत्तक पुत्र स्व० गजानन्द तेली जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज०
- 2-प्रहलाद पुत्र स्व० राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज०
- 3-केलाश पुत्र स्व० राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज०
- 4-शम्भूदयाल पुत्र स्व० राधेश्याम उर्फ रद्दू जाति तेली निवासी छोटा तख्ता तेलियों की गली टोंक राज०

- अपीलान्ट्स

बनाम

- 1-राधेश्याम साहू पुत्र स्व० श्री रामरख जाति तेली निवासी तेलियों की गली छोटा , तख्ता टोंक राज०
- 2- श्रीमति कमला देवी पत्नि राधेश्याम साहू जाति तेली निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक राज०

-रेस्पोजेण्ट्स

अपील अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 विरुद्ध नगर परिषद टोंक दिनांक के पूर्व आदेश दिनांक 21-12-2012 के अनुसरण में दिनांक 24-12-2012 को बहक रेस्पोजेण्ट्स जारी किये गये अवैध पट्टे को रिन्युअल करने के आदेश दिनांक 17-5-2018 एवं इसके अनुसार जारी किये गये रिन्युअल पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु।



उपरिस्थिति : (1) श्री केलाश चन्द शर्मा अपीलान्ट्स
(2) श्री सै० मजहर आलम अभिभाषक रेस्पोजेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 13-3-2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के मालिकाना हक एवं आधिपत्य के पुश्तेनी मकान वाके छोटा तख्ता तेलियों की गली, टोंक में कोई हक अधिकार नहीं होने के बावजूद रेस्पोजेण्ट्स ने स्वयं को उक्त मकान के एक हिस्से का गलत झूठे एवं गैर कानूनी रूप से मालिक स्वांमी बताते हुए नगर परिषद टोंक के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलिभगत करके गुपचुप तरीके से पूर्व में नगर परिषद टोंक के आदेश दिनांक 21-12-2012 के अनुसार दिनांक 24-12-2012 को स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान 148.18 वर्गगज भूमि का अवैध रूप से पट्टा क्रमांक 122 प्राप्त करके उक्त पट्टे को रिन्युअल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें नगर परिषद टोंक ने दिनांक 17-5-2018 को पट्टा रिन्युअल का अवैध रूप से आदेश जारी कर रिन्युअल पट्टा जारी कर दिया। नगर परिषद टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा इस बाबत पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12-12-2012 इसके अनुसार दिनांक 24-12-2012 को जारी पट्टा रिन्युअल आदेश दिनांक 17-5-2018 एवं इसके अनुसरण में जारी नवीन पट्टा को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोजेण्ट्स ने जिस भूमि का पट्टा बनवाया है, उस भूमि से रेस्पोजेण्ट्स का कोई मालिकाना हक अधिकार नहीं है बल्कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के मालिकाना हक आधिपत्य के पुश्तेनी मकानात बने हुए हैं। जिसमें रेस्पोजेण्ट्स अपनी पूर्वजा गुलाब देवी के समय से परमैसिव पजेशन के आधार पर मात्र रहते हैं। ऐसी दशा में से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। नगर परिषद टोंक द्वारा इस बाबत पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12-12-2012 इसके अनुसार दिनांक 24-12-2012 को जारी पट्टा रिन्युअल आदेश दिनांक 17-5-2018 एवं इसके अनुसरण में जारी नवीनीकृत पट्टा निरस्तनीय है। रेस्पोजेण्ट्स ने प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नगर परिषद टोंक के अधिकारियों कर्मचारियों से साजिश करके उक्त जगह का अपीलान्धीन पट्टा अपने स्वामित्व का कोई दस्तावेज पेश किये बिना अपने स्व० पिता रामरख के नाम की एक जाली एवं फर्जी वसीयत दिनांक 29-3-2001 के आधार पर बनवाया था जिसका एक गवाह मर चुका ओर दूसरा गवाह द्वारका ने उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने का शपथ पत्र न्यायालय में दिया है। विशेष बात यह है कि उक्त जाली एवं फर्जी वसीयत दिनांक 29-3-2001 को आधार बना कर वादग्रस्त स्थल से ही 4-5 मकान दूर स्थित अन्य मकान का भी पट्टा रेस्पोजेण्ट्स के सगे भाई दामोदर ने उसी वसीयत के आधार पर स्वयं को उस मकान का मालिक होना बताकर नगर परिषद टोंक के क्रमांक 116 दिनांक 24-12-2012 को प्राप्त किया था जिसके प्रति आर०टी०आई० के तहत प्राप्त कर दस्तोवजों के साथ संलग्न की जा रही है इसलिए भी नगर परिषद टोंक का आदेश एवं पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोजेण्ट्स की दादी श्रीमति गुलाब देवी हमारे पिता स्व. रोधकश्याम की दूर की रिश्तेदार थी ओर गुलाब देवी ने कतिपय कारणों के चलते अपने पुत्र रामरख सहित स्वयं का मकान छोड़ दिया था उस समय आपसी रिश्तेदारी की वजह से हमारे पिता जी ने श्रीमति गुलाब देवी को उनके मालिकाना हक के वादग्रस्त मकान में एक सीध के तीन कमरों में रहने की अनुमति दी थी, तब से वह अपने पुत्र के साथ उक्त तीन कमरों में परमैसिव पजेशन के तहत रहने लगी, उपरोक्त अनुमति के तहत एक सीध के तीन कमरों में वाग्रस्त मकान में रहते आए हैं किन्तु अपीलान्ट्स का वादग्रस्त मकान में कोई मालिकाना अधिकार नहीं रहा है, इसलिए भी आदेश एवं पट्टा निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोजेण्ट्स के हक में मालिकाना हक के अभाव में हमारे पुश्तेनी मकान का भाग, जिसमें रेस्पोजेण्ट्स मात्र परमैसिव पजेशन से रहते हैं बाबत रेस्पोजेण्ट्स के हक में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सन् 2012 में जारी किया गया पट्टा एवं बाद में इस बाबत पारित रिनिवल आदेश दिनांक 17-5-2018 मय रजिस्टर्ड पट्टा अवैध एवं अवैधानिक होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोजेण्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया कि अपीलान्ट्स ने नगर परिषद टोंक को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि यह कानूनन आवश्यक पक्षकार की परिभाषा में आती है क्योंकि प्रस्तुत अपील नगर परिषद टोंक के आदेश दिनांक 21-12-2012, 24-12-2012, एवं 17-5-2018 को निरस्त करने के लिए पेश की गई है, जिसमें नगर परिषद टोंक की ओर से भी पक्षकार बनारये जाने पर सारवाद जवाब एवं बहस पेश की जा सकती है ओर सही तथ्य श्रीमान के सामने आ सकते थे। परन्तु अपीलान्ट्स ने जानबूझ कर नगर परिषद को पार्टी नहीं बनाया है

जिला कलेक्टर
टोंक

जिसकी वजह से यह अपील चलने योग्य नहीं है ओर कानूनन इसी बिन्दु पर खारिज किया जाने लायक है। अपील मीमो में अंकित तथ्य गलत एवं गैर कानूनी है जैसा कि अपीलान्ट्स प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स का अपनी पूर्वजा गुलाब देवी के समय से परमिसिव पजेशन मानकर चल रहे हैं लेकिन इस परमिसिव पजेशन का अपीलान्ट्स ने न तो कोई आधार बताया है न ही कोई समय सीमा बताई है कि कितने वर्षों से रेस्पोडेण्ट्स इस प्रश्नगत भूमि पर बतौर परमिसिव पजेशन रहते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट्स का यह कथन भी गलत है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नगर परिषद कर्मचारियों से साज करके बिना कोई दस्तोवज पेश किये जाली एवं फर्जी वसीयत दिनांक 29-3-2001 के आधार पर प्रश्नगत पट्टा बनवाया है। अपीलान्ट्स का कथन गलत है कि रेस्पोडेण्ट्स ने जिस भूमि का पट्टा बनवाया है वह भूमि उसके पूर्वजों की पुश्तैनी भूमि है, जिसका शजरा पेश किया है तथा सबूत के तोर पर रेस्पोडेण्ट्स ने नगर परिषद में सन 1961 की वोटर लिस्ट पेश की है, जिसके क्र० सं० 784 मकान पं० 146 में रेस्पोडेण्ट्स के दादा रामकरण पुत्र गोरधन का नाम अंकित है तथा क्र० सं० 786 पर रेस्पोडेण्ट्स के पिता रक्खा उर्फ रामरक्खा नाम अंकित है जो पट्टाधारी राधेश्याम के कमाशः दादा एवं पिता हैं, जिसके प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स राधेश्याम का पुराना कब्जा होना साबित है। इसके साथ-साथ रेस्पोडेण्ट्स पट्टाधारी ने अपने पिता का पुराना राशनकार्ड भी पेश किया है तथा दो बुजुर्ग पडोसी भंवरलाल पुत्र मोतीलाल तेली उम्र 65 साल तथा श्रीमति ग्यारसी देवी बेवा गुलाबचन्द तेली उम्र 70 साल के शपथ पत्र एवं वर्तमान पार्षद श्रीमति शानू एवं पूर्व पार्षद श्री नथ्यूजी सिन्धी का प्रमाण पत्र भी पेश किये हैं, जिसमें उन्होंने रेस्पोडेण्ट्स का शजरा बताते हुए इस मकान को रेस्पोडेण्ट्स का पुश्तैनी होना बताया है इस प्रकार अपीलान्ट्स का यह कथन निरर्थक ओ हाजा है कि रेस्पोडेण्ट्स ने उनके हक में जो पट्टा बनवाया है, वह बिना किसी सबूत के नगर परिषद कर्मचारियों से प्रशासन शहरों के संग अभियान के दरमियान साज करके बनवाया है। रेस्पोडेण्ट्स ने भूमि का अपने हक में जो पट्टा बनवाया है उसकी नगर परिषद टोंक द्वारा वांछित पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है। बकायदा नोटिस उज्रदारी जारी किया गया है जिस पर किसी भी व्यक्ति ने कोई उज्रदारी पेश नहीं की है। तत्पश्चात नगर परिषद ने इस सम्बन्ध में पटवारी एवं नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता से मौके की वास्तविक स्थिति की जाँच करवाई है तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही पूरी करने के पश्चात पट्टा जारी किया है सन 2018 में तो रेस्पोडेण्ट्स ने इस पट्टे को केवल मात्र इसलिए रिनिविल करवाया था कि सन 2012 में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा गया था इसलिए अपीलान्ट्स को कानूनन अब धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस पट्टे के सम्बन्ध में कोई ऐतराज करने से वह एस्टोपड है। जब किसी भूमि का एक बार कोई पट्टा जारी कर दिया जाता है तो उसको अधिकृत अधिकारी के द्वारा निरस्त किए बगैर उसी भूमि का दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस सम्बन्ध में कानून की सुव्यवस्थित व्यवस्था है अतः अपील चलने योग्य नहीं है अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व नगर परिषद टोंक की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में राधेश्याम साहू पुत्र स्व० रामरख व श्रीमति कमला देवी पत्नि श्री राधेश्यात साहू निवासी वार्ड नम्बर 22 तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक को आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा जारी पट्टा दिनांक 24-12-2012 तथा उक्त पट्टे को किये गये रिनिविल दिनांक 17-5-2018 में



५
जिला कलेक्टर
टोंक

विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व नोटिस प्रकाशन का कोई सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो कि पट्टा जारी करने से पूर्व उज्जदारी/आपत्ति आमंत्रित की गई थी। केवल शपथ पत्रों पर ही विश्वास कर पट्टा जारी कर दिया गया है। मकान के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों की जाँच कर तथा दोनों पक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायोचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13-3-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोक